



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2005/भाद्र 30, 1927

No. 256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2005/BHADRA 30, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2005

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (पी एच पी जी बेस) के भारत में आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत

सं.15/14/2005-डीजीएडी.— चूंकि वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 51/1/2001-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पी एच पी जी बेस (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था।

और चूंकि दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 122/2002 -सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. समीक्षा के लिए अनुरोध

चूंकि उपरोक्त नियमों में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी प्राप्त निश्चयात्मक सूचना के आधार

पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के शुल्क को निरंतर लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी सकारात्मक सूचना के आधार पर जिससे समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि होती हो यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन की भरपाई करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है अथवा क्या शुल्क की समाप्ति से या उसमें परिवर्तन करने से क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने अथवा दोनों की संभावना है, बशर्त कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद से एक उचित समयावधि बीत गई हो।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उत्पादक और निर्यातक मै. केनका सिंगापुर कार्पोरेशन (केएससी), सिंगापुर ने लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।

3. समीक्षा के लिए आधार

सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के उत्पादक एवं निर्यातक मै. के एस सी, सिंगापुर ने परिवर्तित परिस्थितियों में समीक्षा के लिए निम्नलिखित आधार सूचीबद्ध किए हैं :-

1. भारत में के एस सी की निर्यात कीमत में अत्यधिक कमी हुई है।
2. सीमाशुल्क 35% से घटाकर 20% कर दिया गया है।
3. पाटन मार्जिन अत्यधिक कम हो गया है और इसलिए मूल जांच में निर्धारित बेंच मार्क में भी इसी तरह कमी की जानी चाहिए।
4. कच्ची सामग्री की कीमत में अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन लागत में अत्यधिक कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य में कमी आयी।
5. कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ में अत्यधिक कमी आयी है जो सामान्य मूल्य में गिरावट के समतुल्य है।

प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए परिस्थितियों में परिवर्तन संबंधी पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं।

4. जांच शुरुआत

परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई निश्चयात्मक सूचना के मद्देनजर लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो जाने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियम 23 के प्रावधान के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं।

दिनांक 20 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 51/1/2001- डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेकर प्राधिकारी एतद्वारा नियमों के अनुसार जांच आरम्भ करते हैं ताकि यह समीक्षा की जा सके कि क्या सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पी एच पी जी बेस के आयातों पर शुल्क को लगातार लगाया जाना पाटन के प्रतिसंतुलन के लिए जरूरी है, शुल्क को समाप्त अथवा परिवर्तित अथवा दोनों कर दिए जाने से क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच तथा वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) है जो कि उल्लिखित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम सूची के अध्याय 29 में शीर्ष सं. 2942.00 और आई टी सी एन एस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। हालांकि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. प्रक्रिया

जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की समाप्ति के लिए शुल्क को जारी रखा जाना आवश्यक है तथा क्या शुल्क के हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों से क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) समीक्षा में दिनांक 20 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० 51/1/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

(ii) इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2005 तक की है। तथापि क्षति विश्लेषण की अवधि, वर्ष 2002-03 से जांच अवधि तक की होगी।

(iii) इस जांच में शामिल देश सिंगापुर है।

(iv) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करें एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली- 110011

फैक्स: 91- 11-23063418; 23062335

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने निवेदन नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन करने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसे जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा।

8. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु किसी प्रकार के अनुरोध लिखित में भेजे जाने चाहिए जो उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस समीक्षा संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाएं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. सार्वजनिक फाइलों का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2005

(Mid-term Review)

Subject : Initiation of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports into India of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from Singapore.

No. 15/14/2005-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), vide Notification No. 51/1/2001-DGAD dated 20th September 2002, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of PHPG Base (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Singapore.

And whereas definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 122/2002-Customs dated 31st October 2002.

2. Request for Review

Whereas the Rules require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for

continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding, the above provision, the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

In terms of the above provision, the producer and exporter M/s Kaneka Singapore Corporation, Singapore (KSC) has filed a request for a changed circumstances mid-term review of the anti-dumping duty in force.

3. Grounds for Review

The producer and exporter of subject goods from Singapore M/s KSC, Singapore has listed the following grounds for changed circumstances review.

1. The export price of KSC to India has significantly reduced.
2. The Customs duty has been reduced from 35% to 20%.
3. The dumping Margin has significantly declined and thus bench mark fixed in the original investigation should be reduced accordingly.
4. The Cost of production has significantly declined in view of significant reduction in raw material price leading to reduction in the Normal value.
5. The profits realized by the company has significantly declined which would be a tantamount to a decline in Normal value.

The Authority has determined that sufficient evidence with regards to change in circumstances exists for the initiation of a mid term review.

4. Initiation

Having regard to the positive information provided by the applicant indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Rule 23 supra.

Having decided to review the final findings notified vide Notification No.51/1/2001-DGAD dated 20th September 2002, the Authority hereby initiates the investigations In terms of the Rules, to review whether continued imposition of the duty on imports of PHPG Base originating in or exported from the Singapore is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

5. Product under consideration

The product involved in the original investigation and the current review is D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) falling under heading No.2942.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS classification. This classification, however, is indicative only and, in no way, binding on the scope of the present investigation.

6. Procedure

The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No.51/1/2001-DGAD dated 20th September 2002.
- (ii) The period of investigation for the purpose of this review will be 1st July 2004 to 30th June 2005. However, trends of injury analysis shall cover the years from 2002-03 to POI.
- (iii) The country involved in this investigation is Singapore.
- (iv) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Anti-Dumping Rules supra shall be *mutatis mutandis* applied in this review.

7. Submission of Information

The exporters in subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD)
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan
New Delhi-110011
Fax No.91-11-23063418; 23062335

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making confidential submissions before the Authority is required to file a non-confidential version of the same, for placing the same in the public folder for inspection by all other interested parties to the investigation.

8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions made by other interested parties before the Designated Authority. In case an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may records its findings on the basis of the facts available to it and makes such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority